

वचिारधाराओं की जंग का शकिार बनते हमारे वशि्वविद्यालय

सन्दर्भ

- भारत में उच्च शकिषा की स्थिति विदनीय है, हमारे वशि्वविद्यालयों में अध्यापकों का अभाव, शकिषा की गुणवत्ता नचिले स्तर पर है, लेकिन कभी इन चीजों की माँग करता छात्रों का हुजूम सड़कों पर नहीं दीखता। कसिी न्यूज़ चैनल के डबिट का हसिंसा नहीं बनता और हमारे नीति निर्माताओं को भी ये समस्याएँ दृष्टिगोचर नहीं होती। कुछ लोगों का मानना है कि हमारे वशि्वविद्यालय परसिर को चारों तरफ से तारों या दीवारों के बाड़ से नहीं बल्कि एक खास वचिारधारा से घेरा जा रहा है, वही कुछ लोगों का मानना है कि पहले से एक खास वचिारधारा के गुलाम हमारे वशि्वविद्यालय अब आज़ाद हो रहे हैं।
- वर्ष 2016 में जवाहरलाल नेहरू वशि्वविद्यालय में भारत वशिधी नारे लगे और हाल ही में दलिली वशि्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में एक सेमिनार के आयोजन के दौरान मार-पीट की घटना हुई, और इन दोनों घटनाओं के बीच के समय में भी देश के वशि्वविद्यालय परसिर शांत नहीं रहे। वस्तुतः इस विवाद में दो पक्ष हैं, एक वह जो वशि्वविद्यालय परसिर को सरकारी कब्जे में लयि जाने की बात कर रहा है और दूसरा वह जो यह मानता है कि हमारे वशि्वविद्यालय पहले से ही वैसे लोगों के कब्जे में है जो नहीं चाहते कि यहाँ से भारतवर्ष को प्रेम करने वाले नागरिक नकिलें। अतः इन बातों पर गौर करना दलिचस्प होगा कि क्या सच में हमारे वशि्वविद्यालयों को क्रेद में लयि जा रहा है? और आगे का रास्ता क्या हो?

सरकार का एर्जेडा थोपा हुआ मानने वालों के तरकः

- इस विवाद में शामिल दो में से एक पक्ष यह मानता है कि केंद्र में मौजूद सरकार एक प्रेक्षक समाज (surveillance society) का निर्माण करना चाहती है, वस्तुतः प्रेक्षक समाज वह अवधारणा है जहाँ कसिी व्यक्ती के जीवन में लगभग हर कदम पर सरकार का हस्तक्षेप होता है, समाज, सरकार के समानांतर सोच वाला बन जाता है और उसके खलिाफ बात करने वाली प्रत्येक आवाज़ को दबा दिया जाता है। ध्यातव्य है कि ऐसा अनय वचिारधाराओं को तलिाजली देकर ही कयिा जा सकता है, अतः सरकार और सरकार के सहयोगियों ने उदारवाद, समाजवाद और नारीवाद जैसे तमाम अवधारणाओं को खारजि करना शुरू कर दिया है, इस क्रम में लोकतंत्र की मूल्यों की बात कौन करे यहाँ तो कानून को हाथ में लेकर वशिधी में उठने वाली हर आवाज़ को दबाया जा रहा है।
- वशि्वविद्यालयों को सरकार के कब्जे में मानने वालों ने मीडिया की भूमिका को लेकर भी नरिशा व्यक्त की है। इन वर्गों का वचिार है कि सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर छात्रों को भड़का रही है ताकि मुख्य समस्याओं से लोगों का ध्यान बँटा रहे। दरअसल, सरकार में समाज के दबे-कुचले वर्ग का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, और सत्ता में बैठे लोगों को डर है कि कहीं यह शोषित वर्ग वैकल्पिक राजनीति का रास्ता तलाश न कर ले, अतः इनकी जड़ों पर प्रहार कयिा जाए और ऐसी व्यवस्था की नींव डाली जाए जसिमें हमारे वशि्वविद्यालयों से ऐसे लोग नकिले ही नहीं।

इन तरकों के नहिितार्थ

- गौरतलब है कि हमारे वशि्वविद्यालयों में भारत के अलग-अलग राज्य, धर्म और जाति से संबंध रखने वाले छात्र पढ़ते हैं। विविधता ही भारत की खूबसूरती है और भारत के वशि्वविद्यालय इसी विविधता के परिचायक हैं। हम भारत की विविधता की बात इस सन्दर्भ में कर रहे हैं कि हाल ही में राजस्थान में महाराणा प्रताप के नाम के बाद 'महान' की उपमा लगाने की बात कही गई है। महाराणा प्रताप की शूरवीरता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता और उन्हें महान की संज्ञा से विभूषित करना कतिना सही है, इस बदिु पर इतिहासकारों की राय अलग-अलग है कनिंतु इस बदिु पर शायद बलिकूल भी दो राय नहीं होगी कि अकबर के नाम से महान की उपमा नहीं हटानी चाहिये, जसिकी बात राजस्थान सरकार कर रही है। इस प्रकार के प्रयासों से हम भारत की विभिन्नता में एकता की ताकत को कमज़ोर कर रहे हैं और वशि्वविद्यालयों के जनि कमरों में ज्ञान-विज्ञान, साहित्य और दर्शन की बातें होनी चाहिये वहाँ अब खड़कियों के काँच टूटने का शोर सुनाई दे रहा है। छात्र जीवन के दौरान विभिन्न वचिारधाराओं के मर्म को समझे बनिा परिपक्वता हासिल नहीं की जा सकती, और एक परिपक्व नागरिक ही बेहतर समाज का निर्माण करता है। अतः छात्रों को कसिी एक वचिारधारा, चाहे वह पूंजीवाद हो या समाजवाद, का गुलाम बनने को मज़बूर करना उचित नहीं कहा जा सकता।

वशि्वविद्यालयों को देश-वशिधी ताकतों के गरिफ़्त में बताने वालों के तरकः

- इस पक्ष के लोगों का मानना है कि राष्ट्रवाद को अराजकता का नाम दिया जा रहा है जो कि गलत है। वस्तुतः राष्ट्रवाद के मुख्यतः तीन आयाम हैं। एक वह जो जर्मनी में देखने को मलिा, दूसरा वह जसिने फ़्रांस में राज्य और राष्ट्र प्रथम की भावना का संचार कयिा और तीसरा राष्ट्रवाद वह है जसिमें तथ्यों की चयनात्मक व्याख्या के आधार पर लोगों का धरुवीकरण करके सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य होता है। हालाँकि भारत का संविधान जसि भारत की बात करता है वह राष्ट्रवाद की इन तीनों ही व्याख्याओं से परे है। दरअसल जसि भारतवर्ष से लोगों की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं उसकी बात प्राचीन काल से ही होती आ रही है। गौरतलब है कि भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले कालदिस, स्वामी विविकानंद तब से भारतवर्ष की बात करते आ रहे हैं जब यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म भी नहीं हुआ था। 'भारत फ़रस्ट' के समर्थन में खड़े लोगों का यह मानना है कि यूरोप के राष्ट्रवाद और भारत के राष्ट्रवाद में अंतर है। भारत में राष्ट्रवाद यूरोप की तरह एक कल्पना मात्र होने के बजाय एक प्राकृतिक भावना है। भारतीय उच्च शकिषा व्यवस्था में

ऐसे लोग बैठे हैं जो भारतीयता के इस प्राकृतिक भाव को ही नकारते आ रहे हैं।

इन तर्कों के नहितार्थ

- राष्ट्र की परिभाषा एक ऐसे जन समूह के रूप में की जा सकती है जो कएक भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहता हो, समान परम्परा, समान हितों तथा समान भावनाओं से बँधा हो और जिसमें एकता के सूत्र में बांधने की उत्सुकता तथा समान राजनैतिक महत्त्वाकांक्षाएँ पाई जाती हों। राष्ट्रवाद के नरिणायक तत्त्वों में राष्ट्रीयता की भावना सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। राष्ट्रीयता की भावना किसी राष्ट्र के सदस्यों में पाई जाने वाली सामुदायिक भावना है। हमें इस भावना का सम्मान करना चाहिये क्योंकि व्यापक समस्याओं का सामना हम एक राष्ट्र के तौर पर ही कर सकते हैं।
- हम जब भारत के विधिता को संरक्षित रखने की बात करते हैं तो प्रायः यह तथ्य गौण हो जाता है कि भारतीयता की भावना भी भारतीय विधिता की एक खास उपलब्धि है और इस परिपक्ष में 'भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी' जैसे नारों को न्यायसंगत नहीं उहराया जा सकता। अभवियक्ति की आज़ादी के नाम पर विभाजनकारी तत्त्वों के कृत्य को भारतीय भावना के खिलाफ कार्य करने से रोकना चाहिये। हालाँकि गलत करने वाले को रोकने के लिये गलत रास्ता अख्तियार करना भी उचित नहीं है, अतः कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने की ज़रूरत है चाहे वह किसी भी विचारधारा से संबंध क्यों न रखता हो।

निष्कर्ष

- गौरतलब है कि लिफ्ट और राईट की इस जंग में सबसे अधिक प्रभावित वे लोग हो रहे हैं जो निष्पक्ष सोचना चाहते हैं और निष्पक्ष मूल्यों को अंगीकृत करना चाहते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों से एक से बढ़कर एक राजनेता निकले हैं, लेकिन आज विश्वविद्यालयों में राजनीतिक सूत्र गरिता जा रहा है, देश की तमाम बड़ी पार्टियों के नेता अब संसद से निकलकर विश्वविद्यालय परिसर के टी-स्टालों के इर्द-गिर्द डेरा जमाए हुए हैं। मीडिया के कैमरे भी अक्सर विश्वविद्यालयों के गश्त लगाते रहते हैं। आज के छात्रों में जागरूकता अधिक है जबकि जानकारी कम है। ऐसा इसलिये है कि उसे स्वतंत्र रूप से सीखने और सोचने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। राजनीति, विचार-विमर्श, तर्क-वितर्क सब चलते रहने चाहियें लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों को विचारधाराओं के इस विघटनकारी जंग से बचाना होगा।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/our-universities-becoming-victim-of-war-of-ideology>

